RAJYA SABHA

Thursday, the 9th December, 1999/18 Agrahayana, 1921 (Saka)

The House met at eleven of the clock

Mr. Chairman *in the chair*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Mandari Disease on Coconut Trees

*161. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a dreaded "Mandari" disease which has affected about 90 per cent of the coconut trees in Kerala;

(b) if so, the details and estimated loss due to this disease;

(c) whether Kerala Government has requested the Union Government to release an emergency grant of Rs. 100 crores by treating the Mandari affliction as a natural calamity; and

(d) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Government of Kerala have informed that the coconut mite has affected approximately 500.25 lakh coconut palms in 11 districts of the State, having severe infestation in Trissur and Ernakulam districts. According to the field estimate of the State Directorate of Agriculture, this would be approximately 25% of the coconut palms in Kerala.

Government of Kerala have sent a project proposal requesting for financial assistance of Rs. 100.00 crores in this regard.

The Project proposal of Kerala envisages carrying out massive

spraying operations in an intensive manner in the affected plantations to manage the pest population and prevent spread of coconut mite to newer areas. It is proposed to undertake spraying operations covering 5 crores palms in 11 districts of Kerala, including both prophylactic and curative measures. Three rounds of spraying operations have been planned in a period of seven months starting from November, 1999 to May, 2000. As per recommendations of Kerala Agricultural University, Dicofol or Neem-oil and Garlic Emulsion would be used for effective control of mite. The average cost of chemicals and cleaning and application charges is approximately Rs. 3 and Rs. 10 per palm, respectively. Thus, in order to cover 500 lakh palms, the total financial involvement will be Rs. 195 crores. An amount of Rs. 95 crores is proposed to be met by way of contribution from the State Government, Local Bodies and from farmers.

The request of Government of Kerala for financial assistance of Rs. 100 crores is being examined.

SHRI J. CHITHARANJAN: Sir, I am happy to note that the hon. Minister had taken note of the problem, and he has understood the seriousness of the problem. But, unfortunately, he has not taken a decision to give any financial assistance. What has been said is: "The request of Government of Kerala for financial assistance of Rs. 100 crores is being examined. Sir, this is a very serious disease which has affected coconut trees in almost 11 districts out of the 14 districts in Kerala, and it is spreading at an alarming rate. There is a possibility of that disease spreading to the nearby States, namely, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Therefore, there is an immediate necessity to face this problem on a war-footing. The Kerala Government has already taken certain steps. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether he would give the required financial assistance to the Kerala Government, and a decision in that regard would be taken within a few days.

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, इस डिज़ीज़ से केरल में बहुत नुकसान हो रहा है। केवल केरल में ही नहीं, बल्कि केरल के अगल-बगल के राज्यों में जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पांडिचेरी में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। महोदय, केरल में 25 प्रतिशत कोकोनट ट्रीज़ इससे अफैक्टेड हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली थी, केन्द्र सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए कार्यवाही की थी। पिछले साल भी कोकोनट डेवलपमेंट

बोर्ड के द्वारा इस रोग पर काबू पाने के लिए 96 लाख रुपए की सहायता दी गई थी। यह पैसा पिछली बार खर्च नहीं हो पाया था, इसलिए इस साल के लिए उसको रि-वैलिडेट किया गया है और इस साल उसको खर्च किया जाएगा। सभापति महोदय, यह समस्या काफी गंभीर है। केरल सरकार ने एक प्रस्ताव हमारे पास भेजा है जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की है। जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके द्वारा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक कार्यक्रम चलता है। उस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कार्यक्रम के अंतर्गत एक कंपानेंट है प्लांट प्रमोशन का, जिसके माध्यम के कुछ सहायता दी गई थी लेकिन उसमें भी पैसे की कमी है। इसलिए तत्काल इन्होंने जो 100 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है, उसके बारे में हम लोग अपने स्तर से कार्यवाही करने की कोशिश कर रहे हैं। केरल के मिनिस्टर यहां आए थे, उनसे भी इस बारे में चर्चा हुई है। दूसरे सदन में भी इस पर चर्चा हुई है और हम लोग इस बारे में प्लानिंग कमीशन को लिख रहे हैं कि इनकी समस्या बहुत गंभीर है और उसमें जो ऐलोकेशन है, वह इस रोग से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्होंने जो प्रोग्राम बनाया है, उसके बारे में भी हम अपने स्तर से प्लानिंग कमीशन से चर्चा कर रहे हैं।

SHRI J. CHITHARANJAN: But the hon. Minister has not said the time-limit within which the decision will be taken. Considering the urgency of the matter, the decision will have to be taken at the earliest. That is why I am insisting that he should specify the time-limit within which the decision will be taken.

श्री नीतीश कुमार: इसके लिए अपने स्तर से भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में डिप्टी चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन को भी हमने लिखा है और हम लोगों की यह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इन लोगों को कुछ मदद पहुंचाई जा सके। इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी जितने संसाधन उपलब्ध हैं, उनके द्वारा हम जरूर इनके लिए कुछ कर सकते हैं और हम वे उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, this exotic type of mite is scientifically called Eriophyes querroronis. It first appeared on the face of the world in 1965 in Mexico, at a place called Geurroro. Then, it appeared in 1967 in Cameroon, in 1971 in Columbia, in 1972 in Cuba, in 1975 in Ivory Coast, in 1977 in Puerto Rico, in 1980 in Dominica, in 1989 in Brazil, and in 1990 in Costa Rica. Now, this particular mite has spread to almost all the islands around India. It has appeared in Kerala. It has caused a devastation to about five crore of coconut trees in Kerala and it is spreading to the other States also. Taking into consideration the alarming speed with which it is

spreading and devastating the entire coconut cultivation, and taking also into consideration the fact that this is not a matter concerning Kerala alone—it has national importance — would the Government devise some sort of a national plan to check this devastation of coconut cultivation in India? The Government should try to devise some institutional set-up because such type of pests are coming into India. So, some preventive measures should also be taken. So, I would like to know whether the Government, taking into consideration all these factors, will consider some sort of an all-India action plan to control the spread of this mite and also to help the peasants who are affected by this pest.

श्री नीतीश कुमार: सरकार ऐसा ही कर रही है जो माननीय सदस्य ने सुझाया है। इसके बारे में यहां से साइंटिस्ट गए थे। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी मीटिंग की है और एक स्टीयरिंग कमेटी भी बना दी गई है जो केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और इस सिलसिले में जो माइट को कंट्रोल करने वाली जितनी भी एजेंसी काम कर रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उन सबके बीच एक कोआर्डिनेशन स्थापित किया गया है और उनको यह रोल दिया गया है। जहां तक इस स्प्रेड को रोकने का सवाल है इसके बारे में कुछ सुझाव भी हैं। केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी काम हुआ है और यह डिसीज जहां पहली बार प्रगट हुई थी वहां उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजर्स लिए गए थे उनकी सलाह से और उनसे विचार-विमर्श करके वही मेजर्स यहां भी उठाने की बात हो रही थी। एक जो केरल सरकार ने स्प्रे करने का सजेस्ट किया है, उसमें दो प्रकार की चीजों का वह स्प्रे करना चाहते हैं। लेकिन उसमें यह केमिकल पेस्टिसाईड है। इसके स्प्रे करने का कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए वह 195 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है। लेकिन इसका लास्टिंग सोल्यूशन हो सकता है अगर हम कोई बॉयलोजिकल कंट्रोल इसका करें। इसके लिए एक फंगस आइडेंटिफाई किया चुका है, उसका लेबोरेट्री ट्रॉयल चल रहा है, और अब फील्ड ट्रायल करने की कोशिश होगी। यह सारा काम चल रहा है और इस काम के लिए भी जो हमारी संस्था लगी हुई है उसको तत्काल तीन लाख रुपए दिए गए हैं। लेकिन अभी एक नेटवर्किंग सारे देश की जा रही है और उसमें एक ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि हमारे एन०ए०टी०पी० प्रोजेक्ट से उसको एक करोड़ तक सहायता हम देंगे, सिर्फ बॉयलोजिकल कंट्रोल के लिए और फंगस के काम को आगे बढ़ाने के लिए । जो एक प्रकार का फंगस है—सुटोला, उससे इसका कंट्रोल होता है लेकिन यह एयर बोर्न्ड डिसीज है। यह किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से खत्म होता है इसके बार में यहां के वैज्ञानिकों का कोई निश्चित मत नहीं है। लेकिन दूसरे मुल्कों में जिस प्रकार से इसको कंट्रोल किया गया वही सारे मेजर्स हम यहां भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारे साइंटिस्ट बहुत तेजी से काम कर रहे

हैं। उस समय भी हमने कहा था कि यहां से साइंटिस्टों की टीम फिर भेजी जा रही है और एन०ए०टी०पी० से पैसा देने के लिए मीटिंग करनी है। स्टियरंग कमेटी की वह मीटिंग भी होने जा रही है और सांसदों की एक बैठक भी हुई है। इस काम के लिए लगे हुए वैज्ञानिकों के साथ हम बैठक कर रहे हैं और उसकी मीटिंग 14 तारीख को रखी गई है।

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, this particular disease has been spreading for the last one year. It has created a very, very bad impact on the economy of Kerala because coconut and rubber are the major agricultural crops which sustain the economy of Kerala. Sir, some other disease is spreading in rubber also. This issue would be raised in the House in the near future. The ICAR and the Kerala Agricultural University have been doing research, but no cure for this disease has been found as yet. They have only suggested the use of some chemicals. But that also has been left to the people. Sir, due to the negligence or non-seriousness on the part of the Central and the State Government, no action has been taken either by the ICAR or the Kerala Agricultural University. As a result, the poor people are paying a heavy price. Sir, merely paying them money is not going to solve the problem. I want to know from the hon. Minister two things. Firstly, would the Government compensate the coconut farmers who are cutting their diseased coconut trees? Secondly, if necessary, would the Government seek help from foreign countries who have already treated this disease? Instead of standing on prestige, would the Government do these two things?

श्री नीतीश कुमार: यह काम पूरी तेजी से हो रहा है। हमसे केरल एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के वाईस चांसलर और दूसरे लोग भी मिले थे। केरल के मंत्री भी आए थे दो दिन पहले और यह सारा काम हो रहा है। रिसर्च वर्क इस पर चल रहा है। जैसा मैंने अभी बताया कि लैबोरेटरी ट्रायल्स हो रहे हैं कि उस फंगस को और मल्टीप्लाई करके किस प्रकार से अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह जो स्प्रे किया जा रहा है, दो प्रकार के स्प्रे को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, एक केमिकल पेस्टिसाइड है और दूसरा नीम और गारलिक-पेस्ट पेस्टिसाइड है, उनसे स्प्रे करेंगे। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। जो केरल ने प्रोजेक्ट भेजा है, तीन रुपया कंपोनेंट उसमें होगा,पेस्टिसाइड्स का, लेकिन दस रुपया हर बार के स्प्रे के लिए खर्च होगा और अगले छः महीने के अंदर तीन बार स्प्रे करना होगा। यह तत्काल स्प्रे की बात है लेकिन इसका लास्टिंग सॉल्यूशन हो सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल से ही क्योंकि जो पेस्टिसाइड्स हम देंगे---एक संस्था ने कहा कि रूट में इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए---लेकिन जो कुछ हम देंगे

उसका कोकोनट के पानी पर असर आएगा ही। इसलिए अल्टीमेटली हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल पर जाना होगा और उसके लिए काम चल रहा है, तेजी से काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसलिए महोदय, वैसे ही बैठे रहने का सवाल नहीं है।

श्री टी०एन० चतुर्वेदी: धन्यवाद सभापति महोदय। मंत्री महोदय ने अभी जिक्र किया था कोकोनट कंट्रोल बोर्ड की भूमिका का। मेरे प्रश्न का "अ" भाग यह है कि क्या मंत्री महोदय यह जानकारी देंगे कि कोकोनट कंट्रोल बोर्ड की पुनर्रचना हो चुकी है या नहीं और मेरे प्रश्न का "ब" भाग यह है कि मैंने देखा है कि इसमें वैज्ञानिकों की जगह कोई न कोई स्थानीय नेता या राजनीतिज्ञ ही उसका अध्यक्ष होता है। क्या वे इस बात पर भी विचार करेंगे कि किसी वैज्ञानिक की, जिसे इन समस्याओं की जानकारी हो, नियुक्ति इस स्थान पर की जाए?

श्री नीतीश कुमार: सर, इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है लेकिन जो बात उन्होंने कही है, उसका हम ध्यान रखेंगे।

SHRI E. BALANANDAN: Sir, the explanation given by the Minister is more or less good, but there is a time factor. The Disease is prevailing in Kerala for which the Kerala Agricultural University has found that some medicine has to be applied immediately in order to prevent the spreading of this disease. Sir, the hon. Prime Minister is here. I request that the Government should not waste any more time and see that the financial asistance requested for by the State of Kerala is sanctioned immediately. Sir, in this regard, I want some response from the Prime Minister.

श्री नीतीश कुमार: सर, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि इस मामले में जल्दी करने की जरूरत है इसलिए हम लोग अर्जेंट स्टेप्स उठा रहे हैं।

Legislation for the Welfare of Workers in Fish Processing Industry

*162. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR the pleased to state:

(a) whether Government propose to pass any comprehensive legislation for the welfare of the workers in fish processing industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the details regarding the steps taken by the Government to ensure minimum wage and other benefits for these workers?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No, Sir.